भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2560
8 अगस्त, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा का विकास तथा निर्यात

2560. श्री राम कुमार कश्यप:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में हथकरघा के विकास हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वस्त्र क्षेत्र में निर्यात कम हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) श्रम लागत में वृद्घि तथा पड़ोसी देशों से प्रतिस्पर्धा ने वस्त्र क्षेत्र में भारत के निर्यात को किस सीमा तक प्रभावित किया है; और

(च) बुनाई तथा हथकरघा के निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या कदम उटाए गए हैं?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री अजय टम्टा)

(क)और(ख) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय हथकरघा के विकास और बुनकरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:-

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)
2. व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)
3. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस)
4. यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस)

उपरोक्त योजनाओं के तहत कच्चे माल, करघे व सहायक सामान की खरीद, डिजाइन नवोन्मेष, उत्पाद विविधीकरण, आधारभूत संरचना, कौशल उन्नयन, हथकरघा उत्पादों के विपणन, रियायती दरों पर ऋण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

(ग)से(ड़) वर्ष 2015-16 में 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2017–18 में 18.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कपड़े का निर्यात किया गया । भारत में वस्त्र और परिधान निर्यात में आई मंदी मुख्य रूप से बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि जैसे उभरते देशों से प्रतिस्पर्धा के कारण है, जिनकी उत्पादन लागत कम है और वे प्रमुख बाजारों में वरीयता शुल्क का लाभ उठाते हैं । वस्त्र निर्यात का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

	2015-16	2016-17	2017-18
वस्त्र निर्यात (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	19,030	18,004	18,961

(च) सरकार ने निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए बुनाई सहित परिधान और मेड–अप क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की हैं । पैकेज में परिधान उद्योग के लिए श्रम कानून सुधार, एटीयूएफएस के तहत

अतिरिक्त प्रोत्साहन, वर्धित ड्यूटी ड्रा बैक कवरेज और आयकर अधिनियम की धारा 80जेजेएए के तहत छूट शामिल है ।

*****